



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

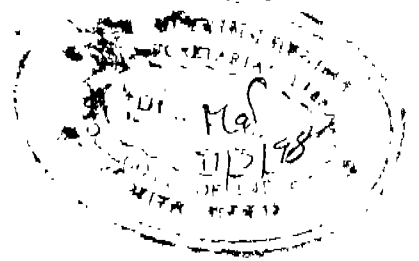
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3— Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 12]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 15, 1998/पौष 25, 1919

No. 12]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 1998/PAUSA 25, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1998

सा.का.नि. 28 (अ).— चूंकि आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन को रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कनाडा की सरकार के बीच हुआ करार उक्त करार के अनुच्छेद 29 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों दो सौविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने पर अधिसूचना जारी करने के पश्चात् 6 मई, 1997 को पवृत्त हो गया है।

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत में लागू किए जाएंगे।

अनुबन्ध

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के

परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

कनाडा की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा कनाडा की सरकार,

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

1. करार के कार्यक्षेत्र**अनुच्छेद - 1****वैयक्तिक कार्यक्षेत्र**

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद -2**करार के अंतर्गत आने वाले कर**

1. यह करार प्रत्येक सौवदाकारी राज्य की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा चाहे ये किसी भी तरीके से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलम्भों पर करों सहित कुल आय, कुल पूंजी पर अथवा आय के या पूंजी के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय और पूंजी पर करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे विशेष रूप से इस प्रकार हैं :-

§क§ भारत के मामले में :

§i§ आयकर जिसमें आयकर अधिनियम के तहत लगाया गया कोई अधिभार शामिल है ;

§ii§ धनकर अधिनियम के तहत लगाया गया धनकर :

§जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है§ ।

§ख§ कनाडा के मामले में :

कनाडा के आयकर अधिनियम के तहत लगाए गए कर, §जिन्हें इसके बाद "कनेडियन कर" कहा गया है§ ;

4. यह करार किसी समरूप अथवा काफी हद तक समान स्वरूप के करों पर भी लागू होगा जो किसी भी सौवदाकारी राज्य द्वारा इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात विद्यमान करों पर उनके अलावा अथवा उनके स्थान पर लगाए जाते हैं ।

5. प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर सौवदाकारी राज्य अपने-अपने संबंधित कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो इस करार के विषय हैं ।

II- परिभाषाएं

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस क़रार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- §क§ "भारत" पद से, जब यह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब इससे अभिप्रेत है - भारत का क्षेत्र, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे का कोई क्षेत्र शामिल है जो अन्तरराष्ट्रीय कानून और भारत के कानूनों के अनुरूप हो और ऐसा क्षेत्र जिसके अन्दर भारत समुद्र तथा उसकी भूमि और अपने प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अधिकारों का प्रयोग कर सकता हो ;
- §ख§ "कनाडा" पद से, जब यह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब इससे अभिप्रेत है - कनाडा का क्षेत्र जिसमें कनाडा के राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे का कोई क्षेत्र शामिल है जो अन्तरराष्ट्रीय कानून और कनाडा के कानूनों के अनुरूप हो और ऐसा क्षेत्र जिसके अन्दर कनाडा समुद्र तथा उसकी भूमि और अपने प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अधिकारों का प्रयोग कर सकता हो ;
- §ग§ "एक सौविदाकारी राज्य" और "दूसरा सौविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षानुसार कनाडा अथवा भारत अभिप्रेत है ;
- §घ§ "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई भागीदारी, कोई कंपनी अथवा कोई अन्य सत्ता §एक न्यास सहित§ शामिल है जिसे एक सौविदाकारी राज्य के क़राधान कानूनों के अंतर्गत एक क़राधेय इकाई माना जाता है ;
- §ङ.०§ "कंपनी" पद से कोई ऐसी निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे एक सौविदाकारी राज्य के क़राधान कानूनों के तहत एक कंपनी अथवा एक निगमित निकाय माना जाता हो ;
- §च§ "एक सौविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे सौविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

§ ६७ § "सक्षम अधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

- § i § कनाडा के मामले में, राष्ट्रीय राजस्व मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- § ii § भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय § राजस्व विभाग § अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ।

§ ६८ § "राष्ट्रीय" पद से अभिप्रेत है :

- § i § दोनों में से किसी एक सौवदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;
- § ii § कोई कानूनी व्यक्ति, भार्गवारी और संस्था जिसे अपनी यह हैसियत एक सौवदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

§ ६९ § "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार कर्नेडियन कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उक्त करों के संबंध में किसी मूल अथवा चक्र के संबंध में देय हो अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड की चोतक हो ;

§ ७० § "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - दोनों में से किसी एक सौवदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी जलयान अथवा वायुयान की कोई यात्रा, सिवाय उसके जब यात्रा का मूल उद्देश्य दूसरे सौवदाकारी राज्य के स्थानों के बीच यात्रियों अथवा माल को लाना-ले जाना हो ।

2 - जहां तक किसी सौवदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी पद का जो इस करार में परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, का अर्थ वही होगा जो उस सौवदाकारी राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के तहत होता है, जो इस करार के विषय हैं ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड से वहां पर कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार तय की जाएगी :-

§क§ उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं, §इसे इसके बाद महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र कहा जाएगा§ ;

§ख§ यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध न हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

§ग§ यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह एक राष्ट्रक है ;

§घ§ यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रक है अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निपटारा करेंगे ।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का निपटारा करने का प्रयास करेंगे । इस प्रकार की सहमति के अभाव में ऐसे व्यक्ति को इस करार के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद -5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- § क § प्रबंध का कोई स्थान ;
- § ख § कोई शाखा ;
- § ग § कोई कार्यालय ;
- § घ § कोई कारखाना ;
- § ङ § कोई कार्यशाला ;
- § च § कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुँआ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- § छ § अन्य लोगों को भण्डारण सुविधा प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में कोई भण्डागारण ;
- § ज § कोई फार्म, बागान अथवा कोई अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागान अथवा उससे संबंधित कार्यकलाप किये जाते हों ;
- § झ § किसी बिक्री केन्द्र के रूप में प्रयुक्त कोई भण्डार अथवा परिसर ;
- § ञ § कोई प्रतिष्ठान अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा विदोहन करने के लिए किया जाता हो, परन्तु ऐसा तभी होगा यदि इनका प्रयोग बारह महीने की किसी भी अवधि में 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए किया जाए ;
- § ट § कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण कार्य, प्रतिष्ठान अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जहां ऐसा भवन-स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप अन्य ऐसे भवन-स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के साथ, यदि कोई हो 12 महीने की किसी भी अवधि में 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए रहते हों ;
- § ठ § किसी उद्यम का कर्मचारियों या अन्य कामियों के माध्यम से किसी सौविदाकारी राज्य के भीतर अनुच्छेद 12 में परिभाषित सम्मिलित सेवाओं को छोड़कर सेवाएं देना, परन्तु ऐसा तभी माना जाएगा यदि :-

§ i§ उस प्रकृति के कार्यकलाप उस राज्य में ऐसी अवधि अथवा अवधियों तक जारी रहें जो 12 महीने की किसी अवधि में कुल मिलाकर 90 दिनों से अधिक हों ; अथवा

§ ii§ अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1 के अर्थ के अंतर्गत सम्बद्ध उद्यम के लिए ये सेवाएं उसी राज्य में की जाएं ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित में से किसी एक को अथवा उससे अधिक को शामिल नहीं माना जाएगा :

- § क§ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के भण्डारण, प्रदर्शन अथवा माल की यदा-कदा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ मात्र सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;
- § ख§ मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा यदा-कदा माल की डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- § ग§ मात्र किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- § घ§ उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं की मात्र खरीद करने अथवा उसके बारे में सूचना एकत्र करने के लिए व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- § ङ§ उस उद्यम के लिए मात्र विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ, जो प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हों, व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हेतुसयत के अधिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक सौधदाकारी राज्य में दूसरे सौधदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि :

- § क§ उसे उस उद्यम की तरफ से प्रामोद्वारित राज्य में सौधदाओं को सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह आदतन ऐसे अधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप पैराग्राफ 3 में उल्लिखित उन कार्यकलापों तक सीमित नहीं हों यदि कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाया ;

§ ५४ § उसके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं हो किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा फण्य-वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो जिसमें से वह नियोजित रूप से उस उद्यम की तरफ से माल अथवा फण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो और जिससे उसे उद्यम की तरफ से उस राज्य में संचालित कृषि आतिरिक्त कार्यकलापों से माल या फण्य-वस्तुओं की बिक्री में सहायता मिली हो ; अथवा

§ ५५ § वह उस उद्यम के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः आदतन आर्डर प्राप्त करता हो ।

5. किसी सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का किसी एक राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । किन्तु किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप उस उद्यम की तरफ से पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः समर्थित हों और उक्त एजेंट तथा उद्यम के मध्य सम-व्यवहार निकट की स्थितियों में नहीं किए जाते तब उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जाएगा ।

6. यदि कोई कंपनी जो एक सौविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे सौविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में § चाहे वह किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा हो § कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी भी कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

III आय का करणान

अनुच्छेद -6

अचल सम्पत्ति से आय

1. सविदाकारी राज्य में अचल सम्पत्ति से आय पर {कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित} कर लगाया जा सकता है जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है ।
2. इस करार के प्रयोजनार्थ "अचल सम्पत्ति" पद को उस सविदाकारी राज्य के कानून और रिवाज के अनुसार परिभाषित किया जाएगा जिसमें प्रश्नाधीन सम्पत्ति है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशु-धन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खानज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्रकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान और विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे ।
3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।
4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यापारिक व्यवसायों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद -7**कारोबार से लाभ**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपयुक्त तरीके से कारोबार करता हो, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो निम्नलिखित के कारण हुए हैं :

§क§ वह स्थायी संस्थापन ; और

§ख§ समान या समरूप प्रकार के माल और पण्य-वस्तुओं की बिक्री तथा समान या समरूप प्रकार के अन्य कारोबार जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से किए जाते हैं।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तो ऐसी स्थिति में वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है। किसी भी हालत में जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों की सही मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता या जिसके अभिनिश्चयन से असाधारण कठिनाइयां पैदा होती हैं वहां स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तर्कपूर्ण आधार पर आकलित किया जाए, बशर्ते कि इस अनुच्छेद में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार ही परिणाम निकले।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा ये उस राज्य के करधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार किए गए हों। तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को पेटेन्टों, तकनीकी जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायटियों, फीस अथवा इससे मिलती-जुलती अन्य अदायगीयों के रूप में अथवा विशेष सेवा निष्पादन के लिए अथवा

प्रबंध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में, यदि कोई रकम वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में अदा की गई हो, तो उसके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभ के निर्धारण में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को पेटेंटों, तकनीकी जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायबिल्टियों, पंजा अथवा इससे मिलती-जुलती अन्य अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा निष्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में प्रभारित की गई हो।

4. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर किसी स्थायी संस्थापन को देने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से बार योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगा। तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा फण्ड-वस्तुएं सौंपी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभ का तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

7. जहां पर लाभ में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेद में अलग से विवेचन किया गया है, वहां पर उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

जहाज़रानी तथा वायु-परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के एक उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
2. पैराग्राफ 1 और अनुच्छेद 7 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के एक उद्यम द्वारा जलयान अथवा वायुयान की यात्रा से प्राप्त लाभों पर, जहां यात्रा का मूल उद्देश्य दूसरे राज्य के स्थानों के बीच यात्रियों अथवा सम्पत्ति को लाना-ले-जाना है, दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों का तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित क्रमशः समुद्र अथवा वायु मार्ग वाले जलयान अथवा वायुयान के स्वामियों अथवा पट्टेदारों अथवा चार्टरों द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन, अथवा माल के परिवहन से प्राप्त लाभों से होगा और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - §क§ दूसरे उद्यम की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री ;
 - §ख§ ऐसे परिवहन से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध कोई कार्यकलाप ; और
 - §ग§ ऐसे परिवहन से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी कार्यकलाप द्वारा आनुबौगिक रूप से प्राप्त जलयानों अथवा वायुयानों का किराया ।
4. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम को जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित है, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के संबंध में प्रयुक्त आधानों के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए §आधानों के परिवहन हेतु ट्रेलरों, बर्गेज और संबद्ध उपकरण सहित§ से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
5. पैराग्राफ 1 और 4 के उपबंध किसी फूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी के भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।
6. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।
7. इस अनुच्छेद के उपबंध किसी ऐसे ड्रिलिंग रिंग अथवा किसी जहाज़ पर लागू नहीं होंगे जिसका मुख्य कार्य माल अथवा यात्रियों के परिवहन से भिन्न काम करना है ।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

§ क § एक सौविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

§ ख § वे ही व्यक्ति, एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे सौविदाकारी राज्य में किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, जहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक सौविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमोक्त राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें इस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रसारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

3. दोनों में से कोई एक सौविदाकारी राज्य अपने राष्ट्रीय कानूनों में दी गई समय-सीमाओं की समाप्ति के पश्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी उद्यम की आय में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और किसी भी हालत में, यह परिवर्तन उस वर्ष के अन्त से पांच वर्ष के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा जिस वर्ष में आय में ऐसे परिवर्तन के कारण उस उद्यम को प्राप्त हुई है, परन्तु पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शर्तों के कारण ऐसा नहीं हो सका है ।

4. पैराग्राफ 2 और 3 के उपबंध धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई चूक अथवा लापरवाही के मामले में लागू नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 10

लभ्यांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लभ्यांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे ।
2. तथापि, ऐसे लभ्यांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लभ्यांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लभ्यांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर अधिक नहीं होगा :

§क§ लभ्यांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत, यदि हितभागी स्वामी एक कंपनी है जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः लभ्यांश अदा करने वाली कंपनी में मताधिकार के कम से कम 10 प्रतिशत को नियंत्रित करती है ;

§ख§ अन्य सभी मामलों में सकल राशि का 25 प्रतिशत ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का प्रभाव उन लभ्यों के संबंध में कंपनी के कराधान पर नहीं पड़ेगा जिनमें से भुगतान किया जाता है ।
4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लभ्यांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारीता के ऋण-दावे नहीं हों, साथ-साथ उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी एक निवासी है ।
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि लभ्यांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है जिसकी लभ्यांश अदा करने वाली कंपनी, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करती है और जिस धारणाधिकार के बारे में लभ्यांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे ।
6. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लभ्यांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लभ्यांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाने हों अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लभ्यांशों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उस दूसरे राज्य में कंपनी के अवितरित लभ्यों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लभ्यांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक सौविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस सौविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, कर लगाया जाएगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी,

§क§ एक सौविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाला और दूसरे सौविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किया जाने वाला ब्याज प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगा, यदि

§i§ ब्याज का आदाता उस सौविदाकारी राज्य की सरकार है अथवा राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसका कोई स्थानीय अधिकरण हो ;

§ii§ ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे सौविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक है;

§iii§ ब्याज, एक एजेंसी अथवा इन्स्ट्रुमेंटेली §एक विवृतीय संस्था संग्रह§ को अदा किया जाता है जिसकी सहमति सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

§ख§ §i§ भारत में उद्भूत होने वाला ब्याज जो कि कनाडा के निवासी को अदा किया जाता है, कनाडा में केवल तभी कराधेय होगा यदि यह निर्यात विकास निगम द्वारा दिए गए, गारंटी किए गए, बीमांकित ऋण अथवा दिए गए, गारंटी किए गए, बीमांकित क्रेडिट के संबंध में दिया जाता है ; अथवा

§ii§ कनाडा में उद्भूत होने वाले ब्याज पर जो कि भारत के निवासी को अदा किया जाता है, केवल भारत में ही कर लगाया जाएगा, यदि यह भारत के निर्यात बैंक §एग्रेम बैंक§ द्वारा दिए गए, गारंटी किए गए, बीमांकित ऋण अथवा दिए गए, गारंटी किए गए, बीमांकित क्रेडिट के संबंध में दिया जाता है ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-उप्युक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण-संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बैंक द्वारा प्रातिभूत हों अथवा नहीं हों, और विशेष रूप से सरकारी प्रातिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रातिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों

से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हो, इसमें वह आय सम्मिलित होगी, जो राज्य के करायान कानून के अंतर्गत दी गई हो, जिसमें आय उत्पन्न होती हो। तथापि, "ब्याज" मव में वह आय सम्मिलित नहीं होगी जो अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 10 में बताई गई है।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, जो एक सौविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे राज्य में, जिसमें ब्याज प्रेद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी सौविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह सौविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्रधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सौविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, सौविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस कसर के अन्य उपबंधों का सम्यक् अनुपालन करते हुए, प्रत्येक सौविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियाँ और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस

1. एक सौवदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाला और दूसरे सौवदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस पर उस सौवदाकारी राज्य में भी, जिसमें वह उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन, यदि रायल्टियों और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, दूसरे सौवदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

§क§ इस अनुच्छेद में यथार्थरूपाधिक सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस और पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ §क§ में उल्लिखित रायल्टियों के संबंध में §इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ §ख§ में वर्णित सेवाओं से भिन्नः :

§i§ प्रथम पंच करावेय वर्षों के दौरान जिसके संबंध में यह कथार प्रभावी है:

§क§ इस अनुच्छेद में यथार्थरूपाधिक रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत, जहां रायल्टियाँ अथवा फीस का अदाकर्ता उस सौवदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-भाग अथवा कोई सार्वजनिक क्षेत्र का कम्पनी हो; और
§ख§ अन्य सभी मामलों में रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 20 प्रतिशत ; और

§ii§ बाद के वर्षों के दौरान, रायल्टियों और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत ; और

§ग§ इस अनुच्छेद में यथार्थरूपाधिक सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस और पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ §ख§ में उल्लिखित रायल्टियों के संबंध में जो कि सम्पत्ति को भोगने के लिए अनुपयोगी और सहायक है, जिसके संबंध में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3§ख§ के अंतर्गत अदायगी प्राप्त की जाती है, सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस अथवा रायल्टियों की सकल राशि का 10 प्रतिशत ।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियों" पद से अभिप्रेत है :

§क§ साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें सिनेमा-फिल्में, फिल्मों पर कार्य, टेप अथवा रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए पुनः निर्माण के अन्य तरीके, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है, इसमें ऐसी किसी सम्पत्ति अथवा अधिकार के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ शामिल हैं, जो उसकी स्थिति अथवा उपयोग, उत्पादकता पर आश्रित है ; और

§ख§ किसी उद्यम द्वारा अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 3§ग§ अथवा 4 और पैराग्राफ 1 में वर्णित क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त की गई अदायगियों से भिन्न किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस" पद का अर्थ किसी व्यक्ति को तकनीकी अथवा परामर्शदायी सेवाएं §तकनीकी अथवा अन्य कार्मिक सेवाओं के प्रवधान के माध्यम सहित§ प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में किसी भी प्रकार की अदायगियों से है, यदि ऐसी सेवाएं :

§क§ ऐसे किसी अधिकार, सम्पत्ति अथवा सूचना जिसके लिए पैराग्राफ 3 में वर्णित अदायगी प्राप्त की जाती है, को लागू करने अथवा भोगने के लिए अनुषंगी और सहायक है ; अथवा

§ख§ ऐसा तकनीकी ज्ञान, अनुभव, कौशल, जानकारी अथवा प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जाती हैं अथवा जिसमें तकनीकी योजना अथवा तकनीकी डिजाइन का विकास अथवा अन्तर्ण शामिल हैं ।

5. पैराग्राफ 4 के होते हुए भी, "सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस" में निम्न पर अदा की गई राशि शामिल नहीं होगी :

§क§ उन सेवाओं के लिए जो सहायक और गौण होने के साथ-साथ पैराग्राफ 3§क§ में वर्णित धक्की से भिन्न सम्पत्ति की धक्की से आनवार्य रूप से जुड़ी हो ;

§ख§ उन सेवाओं के लिए जो सहायक और गौण हों और जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के पारचालन के संबंध में प्रयुक्त जलयानों, वायुयानों, आधानों अथवा अन्य उपकरणों को किराए पर देने से संबंधित हों ;

§ ग § शिक्षण अथवा शैक्षिक संस्थाओं के लिए ;

§ घ § भुगतान करने वाले व्यष्टि अथवा व्यष्टियों के व्यक्तिगत प्रयोग हेतु की गई सेवाओं के लिए ; अथवा

§ ड • § भुगतान करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी अथवा किसी व्यष्टि अथवा व्यावसायिक सेवाओं हेतु व्यष्टियों की फर्म § कंपनी से भन्न § को जैसा कि अनुच्छेद 14 में परिभाषित है ।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक सौंदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे सौंदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा सौंदा के संबंध में रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में, यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

7. एक सौंदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता उस सौंदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-भाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस सौंदाकारी राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सौंदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक सौंदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो

और ऐसी रायल्टियों या सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस उस सौंदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

8. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस की रकम, उसके उपयोग, अधिकार अथवा सूचना जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी, उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमत हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी का आधिक्य भाग, उस करार के अन्य उपबंधों को देखते हुए, प्रत्येक सौंदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कसवेय होगा ।

अनुच्छेद - 13

पैजीगत अभिलम्भ

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों और ऐसे जलयान अथवा वायुयान से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त लाभ पर केवल उस राज्य में कर लगाया जाएगा ।
2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सम्पत्ति के अलावा किसी अन्य सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले लाभ पर दोनों सविदाकारी राज्यों में कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक व्योष्ट अथवा व्योष्टियों की एक फर्म § किसी कंपनी के अलावा § जो कि एक सौविदाकारी राज्य की निवासी है, के द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र क्रिया-कलापों के संबंध में प्राप्त की गई आय केवल उस राज्य में कराधेय होगी । तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी आय पर दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा ; अर्थात् :

§ क § यदि अपने क्रिया-कलापों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए दूसरे सौविदाकारी राज्य में उसके पास नियमित रूप से कोई निश्चित स्थान है या उपलब्ध था, उस मामले में, उस दूसरे सौविदाकारी राज्य में केवल वह आय कराधेय होगी जो कि उस निश्चित स्थान के कारण हुई हो ; अथवा

§ ख § यदि दूसरे सौविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हों ; अथवा

§ ग § यदि दूसरे सौविदाकारी राज्य में सेवाओं के लिए परिश्रमिक उस दूसरे राज्य के निवासियों से प्राप्त किया जाता है अथवा एक स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है जो कि एक व्यक्ति, जो दूसरे सौविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है, दूसरे सौविदाकारी राज्य में रखता है और ऐसा परिश्रमिक संगत वित्त वर्ष में दो हजार पांच सौ कनाडा डालरों § 2500 § अथवा भारतीय मुद्रा में उसके समकक्ष से अधिक हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक, अथवा अध्यापन संबंधी क्रियाकलाप इसके साथ-साथ चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त चिकित्सकों तथा लेखाकारों की सेवाएं शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 15

परवर्तमान वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे राज्य में न किया गया हो । यदि नियोजन इस प्रकार किया जाता है तो वहां से प्राप्त किया गया पारिश्रमिक उस दूसरे राज्य में कराधेय होगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा यदि :

§क§ प्राप्तकर्ता संगत वित्त वर्ष के दौरान ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में रहा हो जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक न हों ;

§ख§ पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया हो, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

§ग§ पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में है ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित जलयान अथवा वायुयान पर दिए गए नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगीयां जो किसी सौविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी कंपनी, जो दूसरे सौविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मण्डल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गयी हो, पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए अपने इस प्रकार के वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत से किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा, जब तक कि मनोरंजनकर्ता, खिलाड़ी अथवा अन्य व्यक्ति यह प्रमाणित नहीं करता कि न तो मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी न ही उनसे संबंधित व्यक्ति उस व्यक्ति के लाभ में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से हिस्सेदार है, इसमें बाद में मिलने वाला परिश्रमिक, बोनस, फीस, तामांश साझेदारी के वितरण अथवा अन्य वितरण भी शामिल हैं ।
3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी का एक संविदाकारी राज्य का दौरा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य, उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्रधिकरण अथवा उस राज्य के सांविधिक निकाय सहित उस राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समर्थित हो ।

अनुच्छेद - 18**पेंशन**

1. एक सौवदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली पेंशन केवल उसी राज्य में कराधेय होगी ।
2. एक सौवदाकारी राज्य में पेंशन उद्भूत हुई समझी जाएगी जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, एक स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. § क § किसी सौविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को किसी अन्य राज्य में § अन्य सौविदाकारी राज्य सहित § उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न, वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के ऐसे पारित्यामिक पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- § ख § तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी अथवा इसी प्रकार के पारित्यामिक केवल दूसरे सौविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे यदि सेवाएं, दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यष्टि उस दूसरे राज्य का निवासी है, जो :
 - § i § उस दूसरे राज्य का राष्ट्रक है ; अथवा
 - § ii § मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, एक सौविदाकारी राज्य अथवा एक राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कारोबार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के पारित्यामिक पर लागू नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षणार्थी

किसी विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु, जो एक सौंपदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे सौंपदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसके द्वारा अपने रख-रखाव, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई अदायगियों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि उसे ऐसे भुगतान उक्त राज्य से बाहर के स्रोतों से किए गए हों ।

अनुच्छेद - 21

अन्य आय

1. एक सौवदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित ~~अन्य~~ संपत्ति से प्राप्त आय से भन्न आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक सौवदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे सौवदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।
3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक सौवदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे सौवदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस राज्य में कर लगेगा । लेकिन किसी संपदा अथवा किसी न्यास ~~से~~ ऐसे किसी न्यास से भन्न, जिसके लिए किए गए अंशदान कर प्रयोजनों के लिए कटौती योग्य थे ~~से~~ से प्राप्त आय के मामले में इस प्रकार से प्रभावित किया गया कर उक्त आय की सकल धनराशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि उक्त आय उस सौवदाकारी राज्य में कराधेय हो, जिसका उक्त लाभानुभोगी निवासी है ।

II पंजी पर करणान

अनुच्छेद - 22

पंजी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में प्रचालित किए गए जहाजों तथा विमानों और ऐसे जहाजों तथा विमानों के प्रचालन से संबंधित चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित की गई पंजी केवल उक्त राज्य में कराधेय होगी ।
2. दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पंजी के सभी अन्य तत्वों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जाएगा ।

IV दोहरे कराधान के निवारण के तरीके

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान को दूर करना

1. दोनों ही सौविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कानून, जहां पर इस करार में उसके विपरीत उपबंध न किए गए हों, संबंधित सौविदाकारी राज्यों में आय पर कराधान को शासित करते रहेंगे ।

2. कनाडा के मामले में, निम्नानुसार दोहरे कराधान का परिहार किया जाएगा :

§क§ कनाडा से बाहर किसी भू-भाग में अदा किए गए कर का कनाडा में संदेय कर में से कटौती करने से संबंधित कनाडा के कानून के मौजूदा उपबंधों और उन उपबंधों में किए गए किसी ऐसे परवर्ती संशोधन - जिससे इसका सामान्य सिद्धांत प्रभावित नहीं होगा - के अनुसार और जब तक कि कनाडा के कानून के अंतर्गत किसी उच्चतर कटौती अथवा राहत की व्यवस्था न की गयी हो, भारत में उद्भूत लाभों, आय अथवा अभिलाभों पर भारत में संदेय कर की कटौती ऐसे लाभों, आय अथवा अभिलाभों के संबंध में संदेय किसी कनेडियन कर में से की जाएगी ।

§ख§ किसी विदेशी संबद्ध कंपनी के छूट प्राप्त अधिशेष का निर्धारण करने के बारे में कनाडा के कानून के मौजूदा उपबंधों और उन उपबंधों में किए गए किसी ऐसे परवर्ती संशोधन जिससे इसका मूल सिद्धांत प्रभावित नहीं होगा - के अनुसार कनेडियन कर की संगणना करने के प्रयोजनार्थ किसी ऐसी कंपनी को, जो कनाडा की निवासी है, अपनी कराधेय आय की संगणना करने में किसी ऐसी विदेशी सहयोगी कंपनी, जो भारत की निवासी है, के छूट प्राप्त अधिशेष में से इसके द्वारा प्राप्त किए गए किसी लाभांश की कटौती की अनुमति दी जाएगी ।

§ग§ जहां पर कनाडा के किसी निवासी के पास ऐसा पूंजी है, जिस पर करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां पर कनाडा द्वारा उक्त निवासी की पूंजी पर कर में से भारत में अदा किए गए उक्त पूंजी कर के बराबर की धनराशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी । लेकिन, इस प्रकार की कटौती उक्त पूंजीकर §कटौती करने से पूर्व यथा-संगणितः के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस पूंजी के बराबर है, जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है ।

§घ§ जहां पर करार के किसी उपबंध के अनुसार कनाडा के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गयी आय अथवा उसके स्वामित्व वाली पूंजी पर कनाडा में कर से छूट प्राप्त है तथापि वहां पर कनाडा द्वारा शेष आय अथवा पूंजी पर आय की धनराशि की संगणना करने में छूट प्राप्त आय अथवा पूंजी को हिसाब में लिया जा सकता है ।

3. भारत के मामले में, निम्नानुसार दोहरे कराधान का परिहार किया जाएगा :-

§क§ भारत के किसी निवासी द्वारा कनाडा के कानूनों के अंतर्गत और करार के उपबंधों के अनुसार कनाडा के भीतर के स्रोतों से आय, जिस पर भारत और कनाडा, दोनों में कर लगाया गया हो, के संबंध में सीधे अथवा कटौती के द्वारा अदा किए गए कनेडियन कर की धनराशि को ऐसी आय के संबंध में संदेय भारतीय कर में खाते डालने की अनुमति दी जाएगी, किंतु यह धनराशि भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी, जो अनुपात भारतीय कर के योग्य उक्त समूची आय में इस प्रकार की आय का बनता हो ।

§ख§ जहां पर भारत के किसी निवासी के पास ऐसी पूंजी है, जिस पर करार के उपबंधों के अनुसार कनाडा में कर लगाया जा सकता है वहां पर भारत द्वारा उक्त निवासी की पूंजी पर कर में से कनाडा में अदा किए गए पूंजी कर के बराबर धनराशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी । लेकिन, ऐसी कटौती उक्त पूंजी पर §कटौती करने से पूर्व यथा-संगणित§ के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उतनी पूंजी के बराबर है, जिस पर कनाडा में कर लगाया जा सकता है ।

वर्तते कि ऐसी आय को लगाए गए कर की दर की संगणना करने में हिसाब में लिया जाए, जिस पर करार के उपबंधों के अनुसार कर नहीं लगाया जा सकता है ।

4. पैराग्राफ 2 §क§ के प्रयोजनार्थ ऐसी किसी कंपनी के संबंध में, जो कनाडा की निवासी है, "भारत में संदेय कर" पदावली में वह धनराशि भी शामिल समझी जाएगी, जो भारतीय कर के रूप में संदेय हो परन्तु निम्नोर्लखित के अंतर्गत स्वीकृत उस वर्ष के लिए कराधेय आय या छूट या कर कटौतों की संगणना में स्वीकृत कटौती शामिल नहीं होगी :

§क§ यथासंशोधित आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10§15§ §iV§, 10क, 32क§जलयानों और विमानों से संबंधित भाग नहीं हैं§ 80जज, 80जज घ और 80 ज क §जलयानों से संबंधित भाग नहीं हैं§, जहां तक वह प्रवृत्त थी और करार पर हस्ताक्षर की तारीख से उन्हें संशोधित नहीं किया गया है या मामूली रूप में हो उन्हें संशोधित किया गया है, जिससे इसकी सामान्य प्रकृति पर कोई प्रभाव न पड़े : या

§ ख § सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकृत कर से छूट या कटौती की रक्षाकृत देने वाले परवर्ती क्रिया दूसरे उपबंध, जो पर्याप्त रूप से इसी तरह का हो, यदि इसे उसके बाद संशोधित न किया गया हो या मामूली रूप से संशोधित किया गया हो जिससे इसकी सामान्य प्रकृति पर कोई प्रभाव न पड़े ।

बशर्ते किसी स्रोत से प्राप्त आय के संबंध में इस पैराग्राफ के कारण कनेडियन कर से राहत नहीं दी जाएगी यदि उस स्रोत के संबंध में यह आय कनाडा के निवासी को पहली बार दी गयी भारतीय कर की छूट या कटौती के बाद दस से अधिक वित्तीय वर्षों से आरंभ होने वाली अवधि से संबंधित हो ।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए सौविदाकारी राज्य के निवासी के लाभों, आय या अभिलामों, जिन पर करार के अनुसार दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा, को उस दूसरे राज्य के स्रोतों से उद्भूत समझा जाएगा ।

[I] विशेष उपबंध

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई करधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी जो उस करधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक समान परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो ।
2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर ऐसा करधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले करधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो ।
3. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को किसी सार्वल स्तर अथवा किन्हीं प्रारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कर प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत छूट, राहत और कटौतियां प्रदान करे जो कि वह अपने निवासियों को प्रदान करता है ।
4. §क§ इस करार की किसी बात से किसी कंपनी, जो भारत की निवासी हो, के कनाडा में स्थायी संस्थापन से प्राप्त आय पर कनाडा की नागरिक कंपनी की आय पर प्रभार्य कर के अलावा कर लगाने से कनाडा को रोकने के रूप में अभिप्रेत नहीं होगा बशर्ते कि इस प्रकार लगाया गया अतिरिक्त कर अनुच्छेद 10 के उप-पैरा 2§क§ में विनिर्दिष्ट ऐसी आय की दर से अधिक न हो, जिस पर पिछले करधान वर्षों में ऐसा अतिरिक्त कर न लगाया गया हो । इस उपबंध के प्रयोजन के लिए "आय" से अभिप्राय है कनाडा में - स्थायी संस्थापन से प्राप्त लाभ, जो कनाडा द्वारा ऐसे लाभों पर इसमें उल्लिखित अतिरिक्त कर के अलावा लगाए गए सभी करों से कटौती करने के बाद एक वर्ष या पिछले वर्षों में प्राप्त किए गए हों ।

इस उप-पैरा के उपबंध ऐसी आय के संबंध में भी लागू होंगे, जो कनाडा में स्थायी संस्थापन के बिना अचल सम्पत्ति के व्यापार को करने वाली किसी कंपनी द्वारा कनाडा में स्थित अचल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त हुई हो बशर्ते इस आय पर अनुच्छेद 6 के उपबंधों या अनुच्छेद 13 के पैरा 2 के अधीन कनाडा में कर लगाया जाता हो ।

§ ख § कनाडा में निवासी कंपनी पर भारत में भारतीय स्वदेशी कंपनियों पर लागू कर से अधिक कर की दर से कर लगाया जाएगा । परन्तु कर दरों का अन्तर 15 प्रतिशत प्वाइंट से अधिक नहीं होगा ।

5. सौंदाकारी राज्यों के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे सौंदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई कर नहीं लगाया जाएगा या इससे संबंधित किसी ऐसी अपेक्षा के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो करधान से अधिक जटिल या अन्य हो और उन अपेक्षाओं से संबंधित हो जो प्रथमोल्लिखित राज्य के इसी प्रकार के दूसरे उद्यमों, जिनकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संपूर्ण या आंशिक रूप से तीसरे राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित हो, पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती हैं ।

6. इस अनुच्छेद में "करधान" का अभिप्राय है वह कर जो इस करार के अंतर्गत आते हैं ।

अनुच्छेद - 25

परस्परिक करार विधि

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है । यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के दो वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसकी वजह से ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के अनुरूप नहीं है ।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपात उचित लगे और यदि वह किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिवार की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा ।
3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कोठनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें परस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे ।
4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए आपस में विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनके बारे में इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है ।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन कर्तों से संबंधित आंतरिक कानूनों §आर्थिक अपवंचन अथवा थोसाथड़ी की रोकथाम करने से संबंधित उनके उपबंधों सहित§ को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों §जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं§ को प्रकट किया जाएगा जो उन कर्तों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों जिन पर यह लागू होता हो । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- §क§ उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- §ख§ ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- §ग§ ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वार्षिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होता हो जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति §आईरे पॉलक§ के प्रतिकूल हो ।

3. यदि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में किसी संविदाकारी राज्य द्वारा सूचना के लिए अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य जिस सूचना के लिए अनुरोध किया गया हो उसे प्राप्त करने का उसी भाँति प्रयास करेगा जैसे कि यह उसके स्वयं के कराधान का मामला हो चाहे दूसरे राज्य को उस समय ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो । यदि किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया हो, तो दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुरोध किए गए अनुसार सूचना प्रदान करने का प्रयास करेगा जैसे कि उस सीमा तक साक्ष्यों के बयान और अराजक दल दस्तावेज §जिसमें किताबें, कागजात, विवरण, अभिलेख, लेखे अथवा लेखा शामिल हैं§ प्रस्तुत करेगा जिस सीमा तक उक्त अन्य राज्य के अपने कर्तों के संबंध में कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अंतर्गत ऐसे बयान एवं दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हों ।

अनुच्छेद - 27**राजनयिक फ़ौज तथा कांसुली अधिकारी**

इस करार से, अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत वर्णित राजनयिक फ़ौजों अथवा कांसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद - 28

विविध नियम

1. इस करार के उपबंधों से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे उक्त राज्य द्वारा लगाये गये कर के निर्धारण में दोनों में से किसी सौवदाकारी राज्य के कानूनों के तहत अब और इसके पश्चात् प्रदान किए गए किसी अपवर्जन, छूट, कटौती, क्रेडिट अथवा अन्य छूट को किसी भांति सीमित करते हैं ।
2. सौवदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी इस करार को लागू करने के प्रयोजन के लिए एक दूसरे के साथ सीधे ही पत्राचार करेंगे ।
3. सेवा और संबंधी व्यापार से सम्बद्ध सामान्य करार के अनुच्छेद xxvii के पैराग्राफ 3 के संबंध में, सौवदाकारी राज्य इस बात से सहमत हैं कि उक्त पैराग्राफ के होते हुए भी किसी ऐसे कर, जिस पर इस करार का कोई उपबंध लागू होता हो, से संबंधित किसी उपाय के बारे में उनके बीच कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे दोनों सौवदाकारी राज्यों की सहमति से ही सेवाओं संबंधी व्यापार परिषद् के समक्ष लाया जाएगा जैसी कि उक्त पैराग्राफ में व्यवस्था की गई है ।

IX अंतिम उपबंध

अनुच्छेद - 29

प्रवृत्त होना

1. संधिदाकारी राज्यों की सरकारें एक दूसरे को अधिसूचित करेंगी कि इस करार को प्रवृत्त करने हेतु संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है ।

2. यह करार पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से परवर्ती अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगा और इसके उपबंध निम्नलिखित ढंग से प्रभावी होंगे :

§ क § भारत में :

§ i § जिस कैलेण्डर वर्ष में करार प्रवृत्त हुआ हो उसके अनुवर्ती वर्ष में अप्रैल माह के पहले दिन अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ; और

§ ii § जिस कैलेण्डर वर्ष में करार प्रवृत्त हुआ हो उसके अनुवर्ती वर्ष में अप्रैल माह के पहले दिन अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अंत में धारित पूंजी के संबंध में ;

§ ख § कनाडा में :

§ i § अनिवासियों को अदा की गई अथवा क्रेडिट की गयी राशियों पर स्रोत पर रोके गए कर के संबंध में जिस कैलेण्डर वर्ष में करार प्रवृत्त हुआ उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली अवधि को ; और

§ ii § जिस कैलेण्डर वर्ष में करार प्रवृत्त हुआ हो उसके अनुवर्ती वर्ष में जनवरी माह के पहले दिन अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले कराधान वर्षों के लिए अन्य कनेडियन कर के संबंध में ।

3. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार जिन करों पर यह करार लागू होता है, उन पर, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के पारहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत सरकार और कनाडा की सरकार के बीच नई दिल्ली में 30 अक्टूबर, 1985 को हस्ताक्षरित करार (बीरो आर्मे, इसके बाद "1985 करार" कहा गया है) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

4. 1985 करार उस अंतिम तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस तारीख से यह इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार प्रभावी हुआ है ।

अनुच्छेद - 30

समापन

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों में से कोई भी संधिदाकारी राज्य जिस कैलेंडर वर्ष से यह करार प्रवृत्त हुआ है उससे पांच वर्ष की समाप्ति के बाद किसी कैलेंडर वर्ष में 30 जून को अथवा उससे पहले दूसरे संधिदाकारी राज्य को इस करार को समाप्त करने की सूचना दे सकता है और उस स्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निःप्रभावी हो जाएगा :-

§क§ भारत में :

- §i§ अगले कैलेंडर वर्ष में अप्रैल की पहली तारीख को या उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष में प्राप्त होने वाली आय के संबंध में ; और
- §ii§ अगले कैलेंडर वर्ष में अप्रैल की पहली तारीख को या उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर धारत पूंजी के संबंध में ।

§ख§ कनाडा में :

- §i§ अगले कैलेंडर वर्ष में जनवरी की पहली तारीख को या उसके बाद अनिवासियों को भुगतान की गई या उनके खाते जमा की गई धनराशि पर स्रोत पर रोके गए कर के संबंध में ; और
- §ii§ अगले कैलेंडर वर्ष में जनवरी की पहली तारीख को या उसके बाद आरम्भ होने वाले कराधान वर्षों के लिए अन्य कर्नाडियन कर के संबंध में ।

असके साथ में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्रधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियानवे के जनवरी मास के ग्यारहवें दिन हिन्दी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक की दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा तीनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं ।

भारत गणराज्य की सरकार

की ओर से

ह./—

(मनमोहन सिंह)

वित्त मंत्री

कनाडा की सरकार

की ओर से

ह./—

(राय मैकलेरन)

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री

प्रीतीकोल

आय एवं पूंजी के संबंध में दोहरे कराधान के पोरहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए कनाडा का सरकार और भारत गणराज्य का सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर करते समय हस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित नीचे दिए गए उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे :

1. यह समझा जाता है कि भारतीय कर के संदर्भ में "वित्तीय वर्ष" पद का अभिप्राय आयकर अधिनियम, 1961 में यथा परिभाषित "पूर्व वर्ष" से है ।
2. यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 6 के पैरा 1 के उपबंध पूंजीगत अभिलामों से भिन्न अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त आय पर भी लागू होते हैं ।
3. यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 5 के पैरा 2§ज§, 2§ट§ या 2§झ§ के उपबंधों के अनुसार जहां दोनों में से किसी भी सौविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे सौविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन है और उक्त पैरा में उल्लिखित समयावधि दो कराधेय वर्षों की है, वहां स्थायी संस्थापन को, उस एक वर्ष में, यदि कोई हो, अस्तित्व में नहीं माना जाएगा, जिसमें उपयोग, स्थल, परियोजना या कार्य, जो भा लियत हो, उस कराधेय वर्ष में तीस दिनों से कम की कुल अवधियों या अवधि के लिए जारी रहता है । स्थायी संस्थापन दूसरे कराधेय वर्ष के अस्तित्व में रहेगा और अनुच्छेद 7 के अनुसार दूसरे सौविदाकारी राज्य में उद्यम पर कर लगाया जाएगा परन्तु यह कर उस दूसरे कराधेय वर्ष के दौरान प्राप्त आय पर ही लगाया जाएगा ।
4. अनुच्छेद 13 के संबंध में यह समझा जाता है कि "अन्तरण" पद में भारतीय कराधान कानूनों के प्रयोजन के अंतर्गत "हस्तान्तरण" शामिल है ।
5. यह समझा जाता है कि करार की किसी भी बात को भागीदारी, न्यास या नियंत्रित विदेशी सम्बद्ध कंपनी के संबंध में उस सौविदाकारी राज्य के निवासी की आय, जिसमें उसका हित है, में शामिल धन-राशि पर कर लगाने से रोकना अभिप्रेत नहीं होगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्रधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियानवे के जनवरी मास के ग्यारहवें दिन हिन्दी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं ।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

कनाडा की सरकार
की ओर से

ह./-
(मनमोहन सिंह)
वित्त मंत्री

ह./-
(राय मैकलेरन)
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री
[अधिसूचना सं. 10503/फा. नं. 505/2/87-एफ.टी.डी.]
के. डी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 1998

G.S.R. 28(E).— Whereas the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Canada stated in Annexure below for the avoidance of double taxation, and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has entered into force on the 6th May, 1997, after the notification by both the Contracting States of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said agreement in accordance with Article 29 of the said agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF CANADA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

WITH RESPECT TO

TAXES

ON INCOME

AND

ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of Canada desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows:

I. SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

(a) in the case of Canada:

the taxes imposed under the Income Tax Act of Canada,

(hereinafter referred to as "Canadian tax");

(b) in the case of India:

(i) the income tax including any surcharge thereon imposed under the Income Tax Act;

(ii) the wealth tax imposed under the Wealth Tax Act;

(hereinafter referred to as "Indian tax").

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.

5. At the end of each year, the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws which are the subject of this Agreement.

II. DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Canada" used in a geographical sense, means the territory of Canada, including any area beyond the territorial seas of Canada which, in accordance with international law and the laws of Canada, is an area within which Canada may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources;
- (b) the term "India" used in a geographical sense, means the territory of India, including any area beyond the territorial seas of India which, in accordance with international law and the laws of India, is an area within which India may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean, as the context requires, Canada or India;
- (d) the term "person" includes an individual, a partnership, a company and any other entity (including a trust) which is treated as a taxable unit under the taxation laws of a Contracting State;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or a body corporate under the taxation laws of a Contracting State;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or his authorized representative;

- (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorized representative;
- (h) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State;
- (i) the term "tax" means Canadian tax or Indian tax, as the context requires, but shall not include any amount payable in respect of any default or omission in relation to the said taxes or which represent a penalty imposed relating to those taxes;
- (j) the term "international traffic" means any voyage of a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or goods between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Agreement.

Article 4

RESIDENCE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question. In the absence of such agreement, such person shall not be considered to be a resident of either Contracting State for the purposes of enjoying benefits under the Agreement.

Article .5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) a store or premises used as a sales outlet;
- (j) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources, but only if so used for a period of more than 120 days in any twelve-month period;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than 120 days in any twelve-month period;
- (l) the furnishing of services other than included services as defined in Article 12, within a Contracting State by an enterprise through employees or other personnel, and only if:
 - (i) activities of that nature continue within that State for a period or periods aggregating more than 90 days within any twelve-month period; or

- (ii) the services are performed within that State for a related enterprise (within the meaning of paragraph 1 of Article 9).

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include any one or more of the following:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display, or occasional delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for other activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State if:

- (a) he has and habitually exercises in the first-mentioned State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make that fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;
- (b) he has no such authority but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, and some additional activities conducted in that State on behalf of the enterprise have contributed to the sale of the goods or merchandise; or,
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise and the transactions between the agent and the enterprise are not made under arm's length conditions, he shall not be considered an agent of independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

III. TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property (including income from agriculture or forestry) may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. For the purposes of this Agreement, the term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:

- (a) that permanent establishment, and
- (b) sales of goods and merchandise of the same or similar kind as those sold, or from other business activities of the same or similar kind as those effected, through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis provided that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed those deductible expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere as are in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than as a reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken

in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Subject to the provisions of paragraph 3, insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and of Article 7, profits derived by an enterprise of a Contracting State from a voyage of a ship or aircraft where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or property between places in the other Contracting State may be taxed in that other State.

3. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by owners or lessees or charterers of ships or aircraft including:

- (a) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises;
- (b) other activity directly connected with such transportation; and
- (c) the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly connected with such transportation.

4. Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

5. The provisions of paragraphs 1 and 4 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

6. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

7. The provisions of this Article shall not apply to a drilling rig or any vessel the principal function of which is the performance of activities other than the transportation of goods or passengers.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any income which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the income of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the income of an enterprise of that State - and taxes accordingly - income on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the income so included is income which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on that income. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

3. A Contracting State shall not change the income of an enterprise in the circumstances referred to in paragraph 1 after the expiry of the time limits provided in its national laws and, in any case, after five years from the end of the year in which the income which would be subject to such change would, but for the conditions referred to in paragraph 1, have accrued to that enterprise.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends;

(b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not affect the taxation of the company on the profits out of which the dividends are paid.

4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are

paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that state, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,
 - (a) interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State if:
 - (i) the payor of the interest is the Government of that Contracting State or of a political subdivision or local authority thereof;
 - (ii) the beneficial owner of the interest is the central bank of the other Contracting State; or
 - (iii) the interest is paid to an agency or instrumentality (including a financial institution) which may be agreed upon in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.
 - (b)
 - (i) interest arising in India and paid to a resident of Canada shall be taxable only in Canada if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by the Export Development Corporation; or
 - (ii) interest arising in Canada and paid to a resident of India shall be taxable only in India if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by the Export-Import Bank of India (Exim Bank).
4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or

debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 8 or in Article 10.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR INCLUDED SERVICES

1. Royalties and fees for included services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for included services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State; but if the beneficial owner of the royalties or fees for included services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 3 and fees for included services as defined in this Article (other than services described in sub-paragraph (b) of this paragraph):

(i) during the first five taxable years for which this Agreement has effect,

(A) 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services as defined in this Article, where the payer of the royalties or fees is the Government of that Contracting State, a political subdivision or a public sector company; and

(B) 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services in all other cases; and

(ii) during the subsequent years, 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services; and

(b) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 3 and fees for included services as defined in this Article that are ancillary and subsidiary to the enjoyment of the property for which payment is received under paragraph 3(b) of this Article, 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services.

3. The term "royalties" as used in this Article means:

(a) payment of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic, or scientific work, including cinematograph films or work on film tape

or other means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, including gains derived from the alienation of any such right or property which are contingent on the productivity, use, or disposition thereof; and

- (b) payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial, or scientific equipment, other than payments derived by an enterprise described in paragraph 1 or Article 8 from activities described in paragraph 3(c) or 4 of Article 8.

4. For the purposes of this Article, "fees for included services" means payments of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or consultancy services (including through the provision of services of technical or other personnel) if such services:

- (a) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in paragraph 3 is received; or
- (b) make available technical knowledge, experience, skill, know-how, or processes or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.

5. Notwithstanding paragraph 4, "fees for included services" does not include amount paid:

- (a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property other than a sale described in paragraph 3(a);
- (b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;
- (c) for teaching in or by educational institutions;
- (d) for services for the personal use of the individual or individuals making the payment; or
- (e) to an employee of the person making the payments or to any individual or firm of individuals (other than a company) for professional services as defined in Article 14.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for included services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or the fees for included services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for included services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Royalties and fees for included services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or the fees for included services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties or the fees for included services was incurred, and such royalties or fees for included services are borne by that permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for included services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for included services, having regard to the use, right, information or services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

2. Gains from the alienation of any property, other than those referred to in paragraph 1 may be taxed in both Contracting States.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual or a firm of individuals (other than a company) who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State. However, in the following circumstances such income may be taxed in the other Contracting State, that is to say:

- (a) if he has or had a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year; or
- (c) if the remuneration for the services in the other Contracting State is either derived from residents of that other Contracting State or is borne by a permanent establishment which a person not resident in that other Contracting State has in that other Contracting State and such remuneration exceeds two thousand five hundred Canadian dollars (\$2,500) or its equivalent in Indian currency in the relevant fiscal year.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician, or an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised in a Contracting State by an entertainer or an athlete accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person which provides the activities in that State, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in that Contracting State unless the entertainer, athlete, or other person establishes that neither the entertainer or athlete nor persons related thereto participate directly or indirectly in the profits of that other person in any manner, including the receipt of deferred remuneration, bonuses, fees, dividends, partnership distributions, or other distributions.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the athlete is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State, including any political subdivision, local authority or statutory body of that other State.

Article 18

PENSIONS

1. Pensions arising in a Contracting State shall be taxable only in that State.
2. Pensions shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Salaries, wages and similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority, in any other State (including the other Contracting State) shall be taxable only in the first-mentioned State.
 - (b) However, such salaries, wages or similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that other State who:
 - (i) is a national of that other State; or
 - (ii) did not become a resident of that other State solely for the purpose of rendering the services.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to salaries, wages and similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

Payments which a student, apprentice or business trainee who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in the first-mentioned State, provided that such payments are made to him from sources outside that State.

Article 21

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles, and arising in the other Contracting State, may be taxed in that other State. However, in the case of income derived from an estate or a trust (other than a trust to which contributions were deductible for tax purposes), the tax so charged shall, provided that the income is taxable in the Contracting State in which the beneficiary is a resident, not exceed 15 per cent of the gross amount of the income.

IV. TAXATION OF CAPITAL

Article 22

CAPITAL

1. Capital represented by ships and aircraft operated by a resident of a Contracting State in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

2. All other elements of capital of a resident of a Contracting State may be taxed in both Contracting States.

V. METHODS FOR PREVENTION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.
2. In the case of Canada, double taxation shall be avoided as follows:
 - (a) Subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions - which shall not affect the general principle hereof - and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada, tax payable in India on profits, income or gains arising in India shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains.
 - (b) Subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the determination of the exempt surplus of a foreign affiliate and to any subsequent modification of those provisions - which shall not affect the general principle hereof - for the purpose of computing Canadian tax, a company which is a resident of Canada shall be allowed to deduct in computing its taxable income any dividend received by it out of the exempt surplus of a foreign affiliate which is a resident of India.
 - (c) Where a resident of Canada owns capital which, in accordance with the provisions of the Agreement may be taxed in India, Canada shall allow as a deduction from the tax on capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the capital which may be taxed in India.
 - (d) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or capital owned by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such

resident, take into account the exempted income or capital.

3 In the case of India, double taxation shall be avoided as follows:

- (a) The amount of Canadian tax paid, under the laws of Canada and in accordance with the provisions of the Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Canada which has been subjected to tax both in India and Canada shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.
- (b) Where a resident of India own capital, which, in accordance with the provisions of the Agreement, may be taxed in Canada, India shall allow as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Canada. Such deduction shall not, however, exceed that part of the capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the capital which may be taxed in Canada.

Provided that income which in accordance with the provisions of the Agreement is not to be subjected to tax may be taken into account in calculating the rate of tax imposed.

4. For the purposes of paragraph 2(a), the term "tax payable in India" shall, with respect to a company which is a resident of Canada, be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under:

- (a) sections 10(15)(iv), 10A, 32A (but not the part dealing with ships and aircraft), 80HH, 80HHD and 80IA (but not the part dealing with ships) of the Income Tax Act, 1961, as amended, so far as they were in force on and have not been modified since the date of signature of the Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character
- (b) any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified

thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

Provided that relief from Canadian tax shall not be given by virtue of this paragraph in respect of income from any source if the income relates to a period starting more than ten fiscal years after the exemption from, or reduction of, Indian tax is first granted to the resident of Canada, in respect of that source.

5. For the purposes of this Article, profits, income or gains of a resident of a Contracting State which are taxed in the other Contracting State in accordance with the Agreement shall be deemed to arise from sources in that other State.

VI. SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4.(a) Nothing in this Agreement shall be construed as preventing Canada from imposing on the earnings of a company, which is a resident of India, attributable to a permanent establishment in Canada, a tax in addition to the tax which would be chargeable on the earnings of a company which is a national of Canada, provided that any additional tax so imposed shall not exceed the rate specified in subparagraph 2(a) of Article 10 of the amount of such earnings which have not been subjected to such additional tax in previous taxation years. For the purpose of this provision, the term "earnings" means the profits attributable to a permanent establishment in Canada in a year and previous years after deducting therefrom all taxes, other than the additional tax referred to herein, imposed on such profits by Canada.

The provisions of this subparagraph shall also apply with respect to earnings from the disposition of immovable property situated in Canada by a company carrying on a trade in immovable property without a permanent establishment in Canada but only insofar as these earnings may be taxed in Canada under the provisions of Article 6 or paragraph 2 of Article 13.

- (b) A company which is a resident of Canada may be subject to tax in India at a rate higher than that applicable to Indian domestic companies. The difference in tax rate shall not, however, exceed 15 percentage points.
5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.
6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case in writing to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within two years from the first notification of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States (including the provisions thereof dealing with the prevention of fiscal evasion or fraud) concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

3. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall endeavour to obtain the information to which the request relates in the same way as if its own taxation was involved notwithstanding the fact that the other State does not, at that time, need such information. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall endeavour to provide information

under this Article in the form requested, such as depositions of witnesses and copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts or writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

MISCELLANEOUS RULES

1. The provisions of this Agreement shall not be construed to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit or other allowance now or hereafter accorded by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State.

2. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of applying the Agreement.

3. With respect to paragraph 3 of Article XXII of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure relating to a tax to which any provision of this Agreement applies falls within the scope of this Agreement may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States.

VII. FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

2. The Agreement shall enter into force upon the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:

(a) in Canada:

(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force; and

(ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;

(b) in India:

(i) in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force; and

(ii) in respect of capital which is held at the end of any fiscal year beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

3. The provisions of the Agreement between the Government of India and the Government of Canada for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at New Delhi on the 30th day of October, 1985 (hereinafter referred to as "the 1985 Agreement") shall cease to have effect with respect to taxes to which this Agreement applies in accordance with the provisions of paragraph 2.

4. The 1985 Agreement shall terminate on the last day on which it has effect in accordance with the foregoing provisions of this Article.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year after the expiry of five years from the year in which it enters into force, give notice of termination to the other Contracting State and in such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in Canada:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January in the next following calendar year; and
- (ii) in respect of other Canadian tax for taxation years beginning on or after the first day of January in the next following calendar year;

(b) in India:

- (i) in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of April in the next following calendar year; and
- (ii) in respect of capital which is held at the end of any fiscal year beginning on or after the first day of April in the next following calendar year.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi, this 11th day of January, 1996 in the English, French and Hindi languages, each version being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

Sd/-

MANMOHAN SINGH
Minister of Finance

FOR THE GOVERNMENT
OF CANADA

Sd/-

ROY MACLAREN
Minister for International Trade

PROTOCOL

At the signing of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Canada for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Agreement:

1. It is understood that the term "fiscal year" in relation to Indian tax, means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961.
2. It is understood that the provisions of paragraph 1 of Article 6, also apply to income, other than capital gains, derived from the alienation of immovable property.
3. It is understood that where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State in accordance with the provisions of paragraphs 2(j), 2(k) or 2(l) of Article 5, and the time period referred to in that paragraph extends over two taxable years, a permanent establishment shall not be deemed to exist in a year, if any, in which the use, site, project or activity, as the case may be, continues for a period or periods aggregating less than 30 days in that taxable year. A permanent establishment will exist in the other taxable year, and the enterprise will be subject to tax in that other Contracting State in accordance with the provisions of Article 7, but only on income arising during that other taxable year.
4. With reference to Article 13, it is understood that the term "alienation" includes a "transfer" within the meaning of Indian taxation laws.
5. It is understood that nothing in the Agreement shall be construed as preventing a Contracting State from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of that Contracting State with respect to a partnership, trust, or controlled foreign affiliate, in which he has an interest.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi, this 11th day of January, 1996 in the English, French and Hindi languages, each version being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

Sd/-

MANMOHAN SINGH

Minister of Finance

FOR THE GOVERNMENT
OF CANADA

Sd/-

ROY MACLAREN

Minister for International Trade

[Notification No. 10503/F. No. 505/2/87-F.T.D.]

K. D. GUPTA, Jt. Secy.

